



वशिव पर्यावास दविस 2023 और भारत का शहरी परदृश्य

प्रलिमिस के लयि:

वशिव पर्यावास दविस, संयुक्त राष्ट्र, यू.एन.-हैबटिट स्करॉल ऑफ ऑनर अवार्ड, स्मार्ट सटीज़, AMRUT मशिन, स्वच्छ भारत मशिन-शहरी, HRIDAY योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम

मेन्स के लयि:

वर्तमान में भारत में शहरी परदृश्य से संबंधित प्रमुख चुनौतियों, आर्थिक सुधार में शहरों की भूमिका

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वशिव पर्यावास दविस के उपलक्ष्य में 9 अक्टूबर, 2023 को वजिज़ान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। शहरी विकास, संधारणीयता और भारत के आर्थिक विकास में शहरों के योगदान पर केंद्रित वशिव पर्यावास दविस की अवधारणा ने चुनौतियों एवं उपलब्धियों की एक लंबी यात्रा तय की है।

वशिव पर्यावास दविस:

- परचिय: संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को वशिव पर्यावास दविस के रूप में नामित किया है जो हमारे आवासों की स्थिति और सभी के लयि पर्याप्त आश्रय के मूल अधिकार को प्रतबिबिति करता है।
 - इस दविस का उद्देश्य वशिव को यह याद दलाना है कि हम सभी के पास अपने शहरों एवं कस्बों के भवषिय को आकार देने की शक्ति और ज़मिमेदारी है।
- शुरुआत: वशिव पर्यावास दविस पहली बार वर्ष 1986 में केन्या के नेरोबी में मनाया गया था। पहले वशिव पर्यावास दविस का वषिय 'आश्रय मेरा अधिकार है' था, जो शहरों में अपर्याप्त आश्रय की गंभीर समस्या पर केंद्रित था।
- वर्ष 2023 की थीम: 'लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएँ, विकास और बहाली के चालक के रूप में शहर' है।
 - वर्ष 2023 शहरी अर्थव्यवस्थाओं के लयि चुनौतीपूरण रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर लगभग 2.5% रह गई है और वर्ष 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 संकट तथा वर्ष 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट के अतिरिक्त यह वर्ष 2001 के बाद सबसे नमिन वृद्धि दर है।

नोट: संयुक्त राष्ट्र मानव अधवासन कार्यक्रम द्वारा वर्ष 1989 में यू.एन.-हैबटिट स्करॉल ऑफ ऑनर अवार्ड की शुरुआत की गई थी। यह वर्तमान में वशिव का सबसे प्रतषिठित मानव अधवासन पुरस्कार (ह्यूमन सेटलमेंट अवार्ड) है।

आर्थिक सुधार में शहरों की भूमिका:

- आर्थिक विकास के वाहक: देश की GDP में महत्त्वपूरण योगदान देने वाले शहरों को आर्थिक विकास का प्रमुख वाहक माना जाता है।
 - शहरी क्षेत्र अर्थव्यवस्थाओं के उत्पादक केंद्र हैं जो वशिव के सकल घरेलू उत्पाद का 75% से अधिक उत्पन्न करते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले व्यवसायों, प्रतभिओं और नवियों को आकर्षित करते हैं।
- रोज़गार के अवसर: शहरों में रोज़गार की वविधिता कुशल और अनेक क्षेत्रों से संबंधित कार्यबल को आकर्षित करती है।
 - आर्थिक सुधार की अवधि के दौरान बेरोज़गारी को कम करने और यहाँ रहने वालों का समग्र देखभाल करने में शहरों की महत्त्वपूरण भूमिका होती है।
- नवाचार और प्रौद्योगिकी केंद्र: देश के कई शहर नवाचार व प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र हैं।

- इन शहरों में मौजूद **अनुसंधान केंद्र, विश्वविद्यालय और तकनीक कंपनियों** तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के साथ ही नवाचार केंद्रित विकास के माध्यम से आर्थिक सुधार को बढ़ावा देती हैं।
- **बुनियादी ढाँचा विकास:** आर्थिक सुधार चरणों के दौरान शहरों को बुनियादी ढाँचा के निर्माण हेतु अक्सर पर्याप्त निवेश प्रदान किया जाता है।
 - **परिवहन, उपयोगिता संबंधी और सार्वजनिक सेवाओं** में किये जाने वाले इन निवेशों से न केवल तत्काल रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है बल्कि इससे दीर्घकालिक उत्पादकता एवं जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाने में भी मदद मिलती है।
- **सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े उद्योग:** शहरों सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े उद्योगों के विकास के लिये सबसे उपयुक्त हैं, ये **पर्यटन, कला** तथा **मनोरंजन** के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं।
 - ये क्षेत्र न केवल राजस्व उत्पन्न करते हैं बल्कि **शहरों को वैश्विक स्तर पर आकर्षक और प्रतिस्पर्धी भी बनाते हैं।**

भारत में वर्तमान शहरी परदृश्य:

- **स्थिति:**
 - भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिसके विकास को यहाँ के शहरों से गति मिलती है।
 - राष्ट्रीय **सकल घरेलू उत्पाद** में शहरों का योगदान **66%** है, **वर्ष 2050 तक यह संख्या बढ़कर 80% होने** की उम्मीद है।
- **वर्तमान प्रमुख चुनौतियाँ:**
 - **अधिक जनसंख्या और तीव्र शहरीकरण:**
 - भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन/प्रवासन करता है।
 - यह तीव्र **शहरीकरण** शहरी संसाधनों और बुनियादी ढाँचे पर अत्यधिक दबाव डालता है।
 - **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:**
 - **आवास: कफियाती आवास** की कमी के परिणामस्वरूप झुग्गी और अनौपचारिक बस्तियों का विकास होता है, जहाँ रहने की स्थिति प्रायः घटिया होती है।
 - **जल आपूर्ति और स्वच्छता:** कई भारतीय शहर अपने निवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल एवं उचित स्वच्छता सुविधाएँ प्रदान करने के लिये संघर्ष करते हैं।
 - इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ और जल नकियों का प्रदूषण होता है।
 - **परिवहन:** भीड़भाड़ वाली सड़कों और कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों की कमी यातायात की भीड़, **प्रदूषण** एवं यात्रा के समय में वृद्धि में योगदान करती है।
 - **पर्यावरण नमिनीकरण:**
 - **वायु प्रदूषण:** कई भारतीय शहर वायु प्रदूषण के उच्च स्तर से पीड़ित हैं जिससे श्वसन संबंधी बीमारियाँ होती हैं और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है।
 - **जल प्रदूषण:** औद्योगिक निर्वहन, सीवेज और **अनुचित अपशिष्ट नपिटान** जल नकियों को प्रदूषित करते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रभावित होता है।
 - **असमानता और सामाजिक वषिमताएँ:**
 - आर्थिक वषिमताएँ: भारत के शहरी क्षेत्रों में आय असमानताएँ देखी जा रही है, जिसमें अमीर और निरधन के बीच अंतर बढ़ रहा है।
 - सेवाओं तक पहुँच: कई शहरी निवासियों के पास स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच नहीं है, जिससे कल्याण एवं जीवन की गुणवत्ता में असमानताएँ उत्पन्न होती हैं।
 - **अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन:** अकेले शहरी भारत में प्रतिदिन लगभग 0.15 मिलियन टन **नगरीय ठोस अपशिष्ट** का उत्सर्जन होता है।
 - भारत सरकार के अनुसार, भारत में उत्पन्न लगभग 78% सीवेज अनुपचारित रह जाता है जिसका नपिटान नदियों, झीलों या समुद्र में किया जाता है।
 - यदि मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और प्रबंधन रणनीतियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तो अपशिष्ट की मात्रा वर्ष 2031 तक 165 मिलियन टन तथा वर्ष 2050 तक 436 मिलियन टन तक पहुँच जाने का अनुमान है।
 - **जल की कमी:** शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भू-जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे कई शहरों में वषिषकर शुष्क मौसम के दौरान जल की कमी हो रही है।
 - **जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता:** शहरी क्षेत्र वषिष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं, जैसे अत्यधिक तापमान, बाढ़ और **तीव्र उष्ण द्वीप**, जो पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं।

शहरी विकास से संबंधित सरकारी पहलें:

- **स्मार्ट शहर**
- **अमृत मशिन**
- **अमृत मशिन**
- **स्वच्छ भारत मशिन-शहरी**
- **हृदय (HRIDAY)**
- **प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी**
- **आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम**

आगे की राह

- एकीकृत शहरी योजना: व्यापक शहरी योजनाएँ विकसित करने की आवश्यकता है जो दीर्घकालिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रत्यासूचना और संसाधनों के संतुलित उपयोग पर विचार करती हैं।
 - इसके अलावा, मशीनरी भूमि उपयोग, कुशल भूमि प्रबंधन और जोनिंग नियमों को बढ़ावा देना चाहिये जो व्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
- शहरी विकास के लिये नवोन्मेषी वित्तीयता: शहर संसाधन जुटाने के लिये नगर नगिम बॉण्ड जैसे नवोन्मेषी वित्तीयता माध्यमों का पता लगा सकते हैं।
 - कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation-AMRUT) के माध्यम से सरकार ने शहरों को पूंजी नविश बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया है।
 - वर्तमान में 12 शहरों ने नगर नगिम बॉण्ड के माध्यम से 4,384 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि एकत्र कर ली है।
- शहरी रोजगार गारंटी: शहरी क्षेत्रों में रहने वाली गरीब आबादी को बुनियादी/मूल जीवन स्तर प्रदान करने के लिये शहरी क्षेत्रों को मनरेगा (MGNREGA) के समान एक योजना की आवश्यकता है।
 - राजस्थान में शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इस दशा में एक अच्छा कदम है।
- उच्च अपशुद्धि प्रबंधन: अपशुद्धि उत्पादन के स्रोत स्थान पर अपशुद्धिों का ध्यानपूर्वक पृथक्करण और अपशुद्धि के औपचारिक पुनः चक्रण एवं उससे खाद बनाने की प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर देने की आवश्यकता है।
 - इसके अतिरिक्त अपशुद्धि निपटान के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये अपशुद्धि-से-ऊर्जा (waste-to-energy) प्रौद्योगिकियों तथा आधुनिक लैंडफिल प्रबंधन में नविश करना चाहिये।
- समावेशी विकास: मूलभूत सेवाओं, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुँच प्रदान करके हाशिये पर मौजूद लोगों और सुभेद्य (कम हो रही) आबादी की जरूरतों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
 - प्रवासी श्रमिकों के हित के लिये प्रवासियों के डेटा को संकलित कर शहरी विकास गतिविधियों में उपयोग करने की आवश्यकता है।
 - साथ ही नविस की स्थिति में सुधार के लिये सामाजिक आवासन और झुग्गी-झोपड़ी/स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता (2004-05 की कीमतों पर प्रतिश्रमिक ₹) में वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई।
2. कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हसिसेदारी में वृद्धि हुई।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में, गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई।
4. ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3 और 4
- (c) केवल 3
- (d) केवल 1, 2 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत में टोस अपशुद्धि प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? (2019)

- (a) अपशुद्धि उत्पादक को पाँच कोटियों में अपशुद्धि अलग-अलग करने होंगे।
- (b) ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे।
- (c) इन नियमों में अपशुद्धि भराव स्थलों तथा अपशुद्धि प्रसंस्करण सुविधाओं के लिये सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं।
- (d) अपशुद्धि उत्पादक के लिये यह आज्ञापक होगा कि किसी एक ज़िले में उत्पादित अपशुद्धि, किसी अन्य ज़िले में न ले जाया जाए।

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारम्बारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए, इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिये। (2016)

प्रश्न. क्या कमज़ोर और पछिड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के दौरान, उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती है? (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/world-habitat-day-2023-and-india-s-urban-landscape>

